प्रेस विज्ञप्ति
30/07/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने 29.07.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स यूनिवर्सल जेम्स के मीत कछाड़िया से संबंधित 204.62 करोड़ रुपये की राशि के प्राकृतिक और प्रयोगशाला में विकसित हीरे के रूप में अपराध की आय को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 132, 135 और 140 के तहत कस्टम अधिकारियों, सूरत द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। वर्तमान मामले में, डीआरआई, सूरत को सूचना मिली थी कि मीत कनुभाई कछाड़िया की स्वामित्व वाली फर्म मेसर्स यूनिवर्सल जेम्स, सूरत एसईजेड, सचिन में एसईजेड संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं का दुरुपयोग करके दो निर्यात खेपों के माध्यम से प्रयोगशाला में विकसित हीरों की आड़ में कटे और पॉलिश किए गए प्राकृतिक हीरे निर्यात करने का प्रयास कर रही थी।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जाँच के दौरान, दोनों निर्यात खेपों की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य के मामले में एकदम गलत घोषणा पाई गई। माल को प्रयोगशाला में विकसित हीरे घोषित किया गया था, जिनकी कीमत 2.93 करोड़ रुपये थी, जबकि भौतिक जाँच के दौरान माल प्राकृतिक रूप से कटे और पॉलिश किए गए हीरे पाए गए, जिनकी कीमत 204.62 करोड़ रुपये थी। इसलिए, इन्हें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ज़ब्त कर लिया गया।

पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, यह पाया गया कि मेसर्स यूनिवर्सल जेम्स के मालिक मीत कनुभाई कछाड़िया कोई वैध व्यवसाय नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल प्राकृतिक हीरों के रूप में बेहिसाब धन/काले धन को प्रयोगशाला में विकसित हीरों के रूप में गलत तरीके से घोषित करके, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं का दुरुपयोग करके निर्यात खेपों के माध्यम से बेहिसाब धन/काले धन को निकालने में शामिल थे। इस गलत घोषणा का उद्देश्य भारी मात्रा में धन (काला धन/बेहिसाब नकदी) को भारत के बाहर छिपाना था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।